केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना

प्रलिमि्स के लयि:

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना

मेन्स के लयि:

[भारत की स्वास्थ्य अवसंरचना]

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने **सभी CGHS लाभार्थियों के लयि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना पैकेज दरों में संशोधन की घोषणा की है** और वीडयिो कॉल सुवधिा प्रदान करके कर्मचारयिों के लयि CGHS रेफरल प्रक्रयिा को सुव्यवस्थति रूप प्रदान कयि है।

- केंद्र सरकार ने आउट-पेशेंट डपिार्टमेंट (OPD)/इन-पेशेंट डपिार्टमेंट (IPD) के लयि परामर्श शुल्क की CGHS दरों को 150 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दयि है और साथ ही ICU शुल्क में संशोधन कर इसे 5,400 रुपए कर दयि गया है।

CGHS में कयि गए हालयिा परविर्तनों के प्रभाव:

- **स्वास्थ्य सेवाओं की लागत:**
  - परामर्श शुल्क, ICU शुल्क और कमरे के करिाये में वृद्धि सहति **CGHS पैकेज दरों में संशोधन से लाभार्थयिों के लयि स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि होने की संभावना है।** जबकि संशोधति दरों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत को कवर करना है, इस कदम से कुछ लोगों के लयि स्वास्थ्य देखभाल का खर्च उठाना अधकि कठनि हो सकता है।
- **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच:**
  - **वीडयिो कॉल रेफरल प्रक्रयिा से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार की उम्मीद है,** खासकर उन लोगों के लयि जन्हिें वेलनेस सेंटर में व्यक्तगित रूप से जाना मुश्कलि है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि यह सरलीकृत प्रक्रयिा लाभार्थयिों के लयि वलिंबता और असुवधिा को कम करके CGHS की दक्षता में वृद्धि करेगी।

CGHS:

- **परचिय:**
  - CGHS एक **व्यापक स्वास्थ्य सेवा योजना** है जसिके तहत केंद्र **सरकार द्वारा अपने कर्मचारयिों, पेंशनभोगयिों और उनके आश्रतिों** को लाभ प्रदान कयि जाता है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1954 में सरकारी कर्मचारयिों और उनके परविारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
- **प्रदान की जाने वाली सुवधिाएँ:**
  - **कल्याण केंद्रों में OPD उपचार**, जसिमें दवाएँ उपलब्ध कराना शामलि है।
  - CGHS से रेफरल के साथ पॉलीक्लनिकि, सरकारी अस्पतालों और CGHS नामांकति अस्पतालों में वशिषज्ञ परामर्श।
  - **कैशलेस उपचार सुवधिाओं के साथ** सरकारी एवं नामांकति अस्पतालों में **पेंशनभोगयिों** के लयि OPD और आंतरकि रोगी उपचार तथा पैनलबद्ध अस्पतालों एवं डायग्नोस्टकि केंद्रों में **चहि्नति लाभार्थयिों के लयि उपचार**।
  - आपात स्थतिमिें सरकारी या नजिी अस्पतालों में हुए **उपचार खर्च की प्रतपिूर्ति**।
  - अनुमति प्राप्त करने के बाद **श्रवण यंत्र, कृत्रमि अंग और उपकरणों की खरीद के लयि कयि गए व्यय की प्रतपिूर्ति**।
  - मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाएँ, परविार कल्याण और चकित्सिा परामर्श।
  - [आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सद्धि औषधि प्रणाली (आयुष)] के तहत दवाओं का वतिरण।
- **उपलब्धयिाँ:**

- वर्तमान में **पूरे भारत के 79 शहरों में लगभग 42 लाख लाभार्थी** CGHS द्वारा कवर किये गए हैं तथा सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिये और अधिक शहरों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सरकारी पहलें:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- आयुष्मान भारत
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
- पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-से 'राष्ट्रीय पोषण मिशन (नेशनल न्यूट्रिशन मिशन)' के उद्देश्य हैं? (2017)

1. गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना।
2. छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना।
3. बाजरा, मोटे अनाज और अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना।
4. मुर्गी के अंडे के उपभोग को बढ़ाना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) केवल 3 और 4

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो आँगनवाड़ी सेवाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ-भारत मिशन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करता है।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission- NNM) का लक्ष्य 2017-18 से शुरू होकर अगले तीन वर्षों के दौरान 0-6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में समयबद्ध तरीके से सुधार करना है।**अतः कथन 1 सही है।**
- NNM का लक्ष्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया/रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच) एवं बच्चों के जन्म के समय कम वज़न की समस्या को कम करना है। **अत: कथन 2 सही है।**
- NNM के तहत बाजरा, बिना पॉलिश किये चावल, मोटे अनाज एवं अंडों की खपत से संबंधित ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।**अत: कथन 3 और 4 सही नहीं हैं।**

अतः विकल्प (a) सही है।

प्रश्न. "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।" विश्लेषण कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2021)

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/central-government-health-scheme